



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 29 दिसम्बर, 2000/३ पौष, 1922

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 29 दिसम्बर, 2000

मंद्या 1-74/2000-वि० स०.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रतियोगी एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक धन (देय की वसूली) विधेयक, 2000 (2000 का

विधेयक संख्या 14) जो आज दिनांक 29 दिसम्बर, 2000 को हिमाचल प्रदेश विधान रामा में पुनः पुरास्थापित किया गया है, सर्व-साधारण की सुवनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

अजय भण्डारी,
सचिव।

2000 का विधेयक संख्यांक 14.

हिमाचल प्रदेश लोक धन (देय की वसूली) विधेयक, 2000

(विधान सभा में पुरस्थापित रूप में)

राज्य सरकार या हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य निगम अथवा सरकारी कम्पनी या बैंककारी कम्पनी के कातिपय देयों की शीघ्र वसूली से भव्यन्वित विधि को पुनःअधिनियमित करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान भवा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक धन (देय की वसूली) अधिनियम, 2000 है ।

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारम्भ ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है ।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

परिभाषाएँ ।

(क) “बैंककारी कम्पनी” से,—

(i) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में यथा परिभाषित बैंककारी कम्पनी ;

(ii) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक ;

(iii) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 में यथा परिभाषित समनुषंगी बैंक ;

(iv) भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित कृषि वित्त निगम सीमित कम्पनी ;

(v) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ;

(vi) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 के अधीन गठित तत्स्थानी नया बैंक ;

(vii) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कोई बैंककारी संस्था ;

(viii) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के अधीन गठित प्रादेशिक ग्रामीण बैंक ; या

(ix) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980 के अधीन गठित तत्स्थानी नया बैंक अभिप्रेत है;

(ख) “कनकटर” से, जिले का कलकटर अभिप्रेत है और इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा कलकटर के कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति इस के अन्तर्गत है ;

(ग) “निगम” से, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 के अधीन स्थापित हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वधीन या नियन्त्रणधीन, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, कोई अन्य निगम भी है ; 1951 का 63

(घ) “वित्तीय सहायता” से, निम्नलिखित के लिए दी गई कोई वित्तीय सहायता अभिप्रेत है,--

- (i) व्यवसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण के प्रयोजनों के लिए ; या
- (ii) आवासिक भवन के निर्माण के लिए ; या
- (iii) पेयजल, कूहल या पाइप लाईन की व्यवस्था करने के लिए ; या
- (iv) पशुपालन, कृषि या बागवानी के विकास के लिए ; या
- (v) किसी ग्रामीण या कुटीर उद्योग, औद्योगिक उपकरण या कृषि उद्योग की स्थापना, विस्तार, आधुनिकीकरण, नवीकरण करने या चलाने के लिए ; या
- (vi) किसी अन्य प्रकार के योजनावद्वारा विकास के प्रयोजनों के लिए ; या
- (vii) विपत्ति से राहत के लिए ; या
- (viii) राष्ट्रीय उधार छात्रवृत्ति स्कीम के अधीन क्रृद्ध के लिए ; या
- (ix) वृत्तिक/विशेषज्ञीय प्रशिक्षण, जैसा राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचित किया जाए, जिसके सम्बन्ध में छात्रवृत्ति/वृत्तिका लोक निधि से संदर्भ की जाती है और राज्य सरकार की संस्थाओं द्वारा दी जाती है;

(ङ) “सरकारी कम्पनी” से, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथा परिभाषित सरकारी कम्पनी अभिप्रेत है और जिसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस रूप में अधिसूचित किया जाता है ; 1956 का 19

(च) “औद्योगिक उपकरण” के अन्तर्गत, माल के विनिर्माण, परिरक्षण, भाग्यारकरण या प्रसंस्करण अथवा खनन या होटल उद्योग अथवा यात्रियों या माल का परिवहन या विद्युत या विद्युत शक्ति के किसी अन्य रूप में उत्पादन या वितरण अथवा मणीनों, यानों, जलयानों, नौकायान, ट्रेलरों या ट्रक्टरों के रख-रखाव, मरम्मत, परीक्षण या सफाई-धुलाई मणीनों या बिजली की सहायता से किन्हीं वस्तुओं के समंजन, मरम्मत या पैकिंग या मठली पकड़ने या उसके रख-रखाव के लिए तट सुविधाओं की व्यवस्था करने या भूमि के किसी संलग्न क्षेत्र का औद्योगिक सम्पदा के रूप में विकास करने या औद्योगिक विकास की अभिवृद्धि के लिए विशेष या तकनीकी जातकारी या अन्य सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए कोई उपकरण है ;

स्पष्टीकरण.—“माल का प्रसंस्करण” पद के अन्तर्गत किसी सामग्री को शारीरिक, यांत्रिक, रसायनिक, विद्युत या इसी प्रकार की अन्य क्रिया के अधीन करके किसी वस्तु के उत्पादन, तैयार करने या बनाने का कोई कार्य या प्रक्रिया है ;

(छ) “प्रायोजित स्कीम” से, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में वह प्रयोजित स्कीम अभिप्रेत है जिसके अधीन सम्बद्ध सरकार या तो,—

(i) निगम या सरकारी कम्पनी को ऋण, अग्रिम, अनुदान या सहायकी के संवितरण के प्रयोजन के लिए या माल के उधार पर या अवक्रप पर विक्रय प्रयोजन के लिए अग्रिम धन देती है; या

(ii) ऋण, अग्रिम, अनुदान या सहायकी के संदाय या उधार पर या अवक्रप पर विक्रीत माल की कीमत के संदाय की प्रत्याभूति देती है या प्रत्याभूति देने के लिए सहमत होती है; और

(च) "राज्य सरकार" से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है।

3. (1) जहां कोई व्यक्ति या तो मूल ऋणी के रूप में या प्रतिभू के रूप में या प्रत्याभूतिदाता के रूप में निम्नलिखित में पक्षकार है—

(क) (i) राज्य सरकार, सरकारी कम्पनी, बैंककारी कम्पनी या निगम द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में उस करार के अधीन दिए गए ऋण, अग्रिम, अनुदान, सहायकी, वित्तीय सहायता, वृत्तिका या छात्रवृत्ति से सम्बन्धी या विक्रीत माल के उधार के बारे में या अवक्रप से सम्बन्धी किसी करार या बंधपत्र का; या

(ii) यथास्थिति, राज्य सरकार, बैंककारी कम्पनी, निगम या सरकारी कम्पनी द्वारा प्रायोजित स्कीम के अधीन दिए गए ऋण, अग्रिम, अनुदान या सहायकी से सम्बन्धी या विक्रीत माल के उधार के बारे में या अवक्रप से सम्बन्धी किसी करार का; या

(ब) ग्रौद्योगिक उपक्रम द्वारा दिए गए ऋण के बारे में राज्य सरकार, सरकारी कम्पनी, बैंककारी कम्पनी या निगम द्वारा दी गई प्रत्याभूति से सम्बन्धी किसी करार का; या

(ग) किसी करार का, जो यह उपबंधित करता है कि द्वीन सरकार को देय कोई धन भू-राजस्व की बकाया के रूप में बमूलीय होगा; या

(ब) राज्य सरकार द्वारा या के माध्यम से दिए गए माल या किसी अन्य वस्तु के विक्रय या वितरण के किसी करार,

और ऐसा व्यक्ति—

(i) ऋण, अग्रिम, वृत्तिका या छात्रवृत्ति का उपकी किसी किस्त या ब्याज के प्रतिसंदाय में कोई व्यतिक्रम करता है; या

(ii) अनुदान की शर्तों के अधीन, अनुदान या उसके किसी प्रभाग का प्रतिदाय करने का दायी होने पर ऐसे अनुदान या उसके प्रभाग या किस्त के प्रतिसंदाय में कोई व्यतिक्रम करता है; या

(iii) माल या किसी अन्य वस्तु की कीमत या उसके ब्याज के संदाय का दायी होने पर, उसके या उसके भाग का संदाय करने में असफल रहता है; या

कतिपय देय की भू-राजस्व की बकाया के रूप में बसूली।

(iv) अन्यथा करार के निवंधनों का अनुपालन करने में असफल रहता है ; तब, राज्य सरकार की दशा में, ऐसा अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, और बैककारी कम्पनी, निगम या सरकारी कम्पनी की दशा में, उसका प्रबन्ध निदेशक या इस निमित्त विनिदिष्टतः प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, वाहे किसी भी नाम से जात हो जो मण्डलीय प्रबन्धक की पंक्ति से नीचे का न हो । तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन वसूली के किसी अन्य ढंग पर प्रतिकल प्रभाव डाले बिना, कलक्टर को, ऐसे व्यक्ति द्वारा देय राशि को वर्णित करते हुए और यह अनुरोध करते हुए प्रमाणपत्र भेज सकेगा कि कार्यवाहियों के खर्च सहित ऐसी कोई राशि या कोई अन्य राशि वसूल की जाए मानो यह भू-राजस्व की बकाया हो ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन भेजा प्रमाण-पत्र उसमें विवरणित विषय का निश्चायक सबूत होगा और कलक्टर ऐसे प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर उसमें विवरणित रकम को भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल करने के लिए कार्यवाही करगा ।

(3) उप-धारा (1) की कोई भी बात, किसी बन्धक, भार, गिरवी या किसी अन्य विलंगम द्वारा सूचित किसी सम्पत्ति में, राज्य सरकार, बैककारी कम्पनी, निगम या सरकारी कम्पनी के हित पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

(4) जहां उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की सम्पत्ति, यथास्थिति, राज्य सरकार, बैककारी कम्पनी, निगम या सरकारी कम्पनी के पक्ष में किसी बन्धक, भार, गिरवी या अन्य विलंगम के अधीन है, वहां तब—

(क) माल की गिरवी की दशा में इस प्रकार गिरवी रखे माल के विक्रय के लिए कार्यवाहियां की जाएंगी और यदि ऐसे विक्रय के आगम, देय रकम से कम है, तो ऐसे व्यक्ति की अन्य सम्पत्ति के विश्व अधिशेष की वसूली के लिए कार्यवाहियां की जाएंगी :

परन्तु जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि, यथास्थिति, इपको या बैककारी कम्पनी, निगम या सरकारी कम्पनी को देय रकम की वसूली की सुरक्षा के लिए ऐसा करना आवश्यक है, तो यह कारणों को अभिलिखित करते हुए तब गिरवी माल से पहले या उसी समय अन्य सम्पत्ति के सम्बन्ध में कार्यवाहियां करने के लिए निदेश दे सकेंगी मानो कार्यवाहियां गिरवी रखे माल के विक्रय के लिए की जाती हैं ।

(ख) स्थावर सम्पत्ति पर बन्धक, भार या अन्य विलंगम की दशा में, यथास्थिति, ऐसी सम्पत्ति या, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति का उसमें हित, उस व्यक्ति से देय राशि की वसूली के लिए कार्यवाहियों में पहले विक्रीत किया जाएगा और अन्य कोई कार्यवाहियां केवल तभी की जा सकेंगी यदि कलक्टर प्रमाणित करे कि प्रथमतः वर्णित प्रक्रिया द्वारा युक्ति-युक्त समय के भीतर देय राशि की वसूली की कोई संभावना नहीं है ।

(5) जहां सरकारी कम्पनी, बैककारी कम्पनी या निगम के देयों के अतिरिक्त, धारा 3 में वर्णित व्यक्ति से सरकारी देय वसूली नहीं हों, वहां भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूली में सरकारी देयों को प्राथमिकता दी जाएगी ।

4. धारा 3 के अधीन कलक्टर की सेवाओं का उपभोग करने वाली कोई बैंककारी संग्रहण कम्पनी, निगम या सरकारी कम्पनी ऐसे दर पर राज्य सरकार को संग्रहण प्रभार संदर्भ करेगी जैसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर, राजपत्र में अधिसूचित किए जाएं। प्रभार।

5. (1) हिमाचल प्रदेश लोक धन (देश की वसूली) अधिनियम, 1973 एतद्वारा निरसित किया जाता है। निरसन और व्यावृत्तियां।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियम के अधीन की गई कोई वात या कारंवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश लोक धन (देय की वसूली) अधिनियम, 1973 (1973 का 22) राज्य, या निगम अथवा सरकारी कम्पनी को संदेय कतिपय देयों की भू-राजस्व की बकाया के रूप में देयों की शीघ्र वसूली के लिए उपबंध करता है। उक्त अधिनियम में अन्तविष्ट विद्यमान उपबंध अनुसूचित बैंकों के देयों की वसूली के लिए उसी रीति में उपबंध नहीं करता है। वर्तमानतः, विभिन्न बैंकों द्वारा ऋणों का भारी बकाया वसूली के लिए लंबित पड़ा है। क्योंकि ऐसी वसूली को विनियमित करने व कानूनों में लम्बी प्रक्रिया का उपबंध होने के कारण, न्यायालय दावों को अन्तिम रूप देने के लिए पर्याप्त समय लेते हैं। इन बैंकों ने राज्य सरकार को उपर्युक्त अधिनियम में उपर्युक्त उपबंध करने के लिए अनुरोध किया है ताकि लंबित वसूलियां भू-राजस्व की बकाया के रूप में शीघ्र की जा सकें। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति स्कीम और राज्य सरकार के संस्थानों द्वारा दी गई वृत्तिक/विशेषज्ञीय प्रशिक्षण के अधीन बंध-पत्र धन या ऋणों की वसूली के लिए उपर्युक्त उपबंध करने का भी प्रस्ताव किया गया है। इस से उपबंधों को पुनर्विलोकित और पुनः अधिनियमित करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

क्रियमाला : 2000.

राजन सुशास्त्र।
प्रभारी मंत्री।

विस्तीर्ण ज्ञापन

इस विधेयक के उपबन्ध अधिनियमित किए जाने पर, राज्य सरकार या हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम या किसी सरकारी कम्पनी अथवा बैंककारी कम्पनी आदि की अपने देयों को भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल करने को सशक्त करेगा। विधेयक में अन्तविष्ट उपबंध अधिनियमित किए जाने पर विद्यमान सरकारी तंत्र द्वारा कार्यान्वयित किए जाएंगे। इसलिए, विधेयक के उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिए राजकोष से कोई भी अतिरिक्त व्यय उपगत नहीं होगा।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 4, राज्य सरकार को, कलेक्टर की सेवाओं का उपभोग करने वाली बैंककारी कम्पनी, निगम या सरकारी कम्पनी द्वारा दी जाने वाली संग्रहण प्रभार की दरों को अधिसूचित करने को सशक्त करता है। यह प्रत्यायोजन आवश्यक और सामान्य स्वरूप का है।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 14 of 2000.

THE HIMACHAL PRADESH PUBLIC MONEYS (RECOVERY OF DUES) BILL, 2000

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to re-enact the law relating to the speedy recovery of certain dues of the State Government or the Himachal Pradesh Financial Corporation or any other Corporation notified by the State Government in this behalf or a Government Company or a Banking Company.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty first Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Public Moneys (Recovery of Dues) Act, 2000.

Short title, extent and comment- cement.

(2) It extends to whole of the State of Himachal Pradesh.

(3) It shall come into force at once.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

Defini- tions.

(a) “Banking Company” means,—

(i) a Banking Company as defined in the Banking Regulation Act, 1949 ;

(ii) the State Bank of India constituted under the State Bank of India Act, 1955 ;

(iii) a subsidiary bank as defined in the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 ;

(iv) the Agricultural Finance Corporation Limited, a company incorporated under the Indian Companies Act, 1956 ;

(v) the National Bank for Agricultural and Rural Development, established under the National Bank of Agricultural and Rural Development Act, 1981 ;

(vi) a corresponding new bank constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970 ;

(vii) any banking institution notified by the Central Government under section 51 of the Banking Regulation Act, 1949 ;

(viii) the Regional Rural Banks constituted under the Regional Rural Banks Act, 1976 ;

(ix) a corresponding new Bank constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1980 ;

(b) “Collector” means a Collector of the District and includes any person appointed by the State Government to perform the functions of a Collector under this Act ;

10 of 1949

23 of 1955

38 of 1959

1 of 1956

61 of 1981

5 of 1970

10 of 1949

21 of 1976

40 of 1980

(c) "Corporation" means the Himachal Pradesh Financial Corporation established under the State Financial Corporation Act, 1951 and includes any other Corporation owned or controlled by the Central Government or the State Government which the State Government may, by notification, specify ;

63 of 1951

(d) "financial assistance" means any financial assistance rendered,—
 (i) for the purposes of vocational or technical training ; or
 (ii) for the construction of residential buildings ; or
 (iii) for providing drinking water, kuhl or pipe line; or
 (iv) for the development of animal husbandry, agriculture or horticulture; or
 (v) for establishing, expanding, modernising, renovating or running any village or cottage industry, industrial undertaking or agro industry ; or
 (vi) for purposes of any other kind of planned development; or
 (vii) for relief against distress; or
 (viii) for loans under the National Loans Scholarship Scheme ; or
 (ix) for professional/specialised training, as may be notified, in the Official Gazette, by the State Government, in relation to which scholarship/stipend is paid out of the public funds and is imparted by the institutions of the State Government ;

(e) "Government Company" means a Government Company as defined in section 617 of the Companies Act, 1956 and which is notified as such by the State Government from time to time;

1 of 1956

(f) "industrial undertaking" includes any undertaking for the manufacture, preservation, storage or processing of goods, or mining, or the hotel industry, or the transport of passengers or goods, or the generation or distribution of electricity or any other form of power or the maintenance, repair, testing or servicing of machinery, vehicles, vessels, motor boats, trailers or tractors or assembling, repairing or packing of any articles with the aid of machinery or power or fishing or providing shore facilities for fishing or maintenance thereof, or for the development of any contiguous area of land as an industrial estate or providing special or technical knowledge or other services for promotion of industrial growth ;

Explanation.—The expression "processing of goods" includes any act or process for producing, preparing or making an article by subjecting any material to a manual, mechanical, chemical, electrical or any other like operation ;

(g) "sponsored scheme" means a scheme sponsored by way of financial assistance by the State Government or the Central Government under which the concerned Government, either—

(i) advances money to the Corporation or the Government Company for the purposes of disbursing loans, advances, grants or subsidies or for the purpose of sale of goods on credit or hire purchase ; or

(ii) guarantees or agrees to guarantee the payment of loan, advances, grant or subsidies or the payment of price of goods sold on credit or hire purchase; and

(h) "State Government" means the Government of Himachal Pradesh.

3. (1) Where any person either as principal or as surety or as guarantor is a party—

(a) (i) to any agreement or bond, relating to a loan, advance, grant, subsidy, financial assistance, stipend or scholarship given under that agreement or relating to credit in respect of, or relating to hire purchase of goods sold by the State Government, Government Company, Banking Company, or Corporation by way of financial assistance ; or

(ii) to any agreement relating to loan, advance, grant or subsidy given under that agreement or relating to credit in respect of, or relating to hire purchase of, goods sold by the State Government, a Banking Company, a Corporation or a Government Company, as the case may be, under a sponsored scheme ; or

(b) to any agreement relating to a guarantee given by the State Government, Government Company, Banking Company or a Corporation in respect of a loan raised by an industrial undertaking ; or

(c) to any agreement providing that any money payable thereunder to the State Government shall be recoverable as arrears of land revenue ; or

(d) to any agreement to sell or distribute goods or any other article supplied by/or through the State Government and such person—

(i) makes any default in the repayment of the loan, advance, stipend or scholarship or any instalment or interest thereof ; or

(ii) having become liable under the conditions of the grant to refund the grant or any portion thereof, makes any default in repayment of such grant or portion or instalment thereof ; or

(iii) having become liable to pay the price of the goods or any other article or interest thereof, fails to pay the same or part thereof; or

(iv) otherwise fails to comply with the terms of the agreement;

then, in case of the State Government, such officers as may be authorised in this behalf by the State Government, by notification in the Official Gazette, and in the case of Banking Company, Corporation or the Government Company, the Managing Director or any other officer not below the rank of Divisional Manager specifically authorised in this behalf, thereof, by whatever name called, may without prejudice to any other mode of recovery under any other law for the time being in force, send a certificate to the Collector, mentioning the sum due from such person and requesting that such sum together with the costs of the proceedings or any other sum be recovered as if it were an arrear of land revenue.

Recovery
of certain
dues as
arrears of
land reve-
nue.

(2) A certificate sent under sub-section (1) shall be conclusive proof of the matter stated therein and the Collector on receiving such certificate shall proceed to recover the amount stated therein as an arrear of land revenue.

(3) Nothing in sub-section (1) shall affect any interest of the State Government, a Banking Company, a Corporation or a Government Company, in any property created by mortgage, charge, pledge or any other encumbrance.

(4) Where the property of any person referred to in sub-section (1) is subject to any mortgage, charge, pledge or other encumbrance in favour of the State Government, a Banking Company, a Corporation or a Government Company, as the case may be, then—

(a) in every case of a pledge of goods, proceedings shall first be taken for the sale of goods so pledged and if the proceeds of such sale are less than the sum due, then proceedings shall be taken for recovery of the balance against the other property of such person:

Provided that where the State Government is of the opinion that it is necessary so to do for safeguarding the recovery of the sum due to it or to a Banking Company, a Corporation or a Government Company, as the case may be, it may, for reasons to be recorded in writing, direct proceedings to be taken against the other property then the goods pledged before or at the same time as the proceedings are taken for the sale of goods pledged.

(b) in every case of a mortgage, charge or other encumbrance on immoveable property, such property or, as the case may be, the interest therein of the person referred to in sub-section (1) shall first be sold in proceedings for recovery of the sum due from that person and any other proceedings may be taken only if the Collector certifies that there is no prospect of realisation of the sum due through the first mentioned process within a reasonable time.

(5) Where Government dues are recoverable from the person mentioned in section 3 in addition to dues of Government Company, Banking Company or Corporation, priority will be given to Government dues in recovery as arrears of land revenue.

4. A Banking Company, a Corporation or a Government Company availing the services of the Collector under section 3 shall pay collection charges to the State Government at such rates, as may be notified in the Official Gazette by the State Government, from time to time.

5. (1) The Himachal Pradesh Public Moneys (Recovery of Dues) Act, 1973 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Act, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Public Moneys (Recovery of Dues) Act, 1973 (Act No. 22 of 1973) makes provisions for speedy recovery of certain dues payable to the State, or Corporation or Government Company as arrears of land revenue. The existing provisions contained in the said Act do not provide for the recovery of dues of the Scheduled Banks in a like manner. At present, huge arrears of loans are lying pending for recovery by various Banks. The courts take considerable time in finalization of the cases because of the statutes regulating such recovery, provide for a lengthy procedure. These banks have made requests to the State Government for making suitable provisions in the aforesaid Act so that the pending recoveries could be effected expeditiously as arrears of land revenue. Further, it has also been proposed to make suitable provision for recovery of bond money or loans under the National Loan Scholarship Scheme and professional/specialised training imparted by the institutions of the State Government. This has necessitated the review and re-enactment of the provisions.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

RAJAN SUSHANT,
Minister-in-Charge.

SHIMLA :
The, 2000.

FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of the Bill, when enacted, will empower the State Government or Himachal Pradesh Financial Corporation or a Government Company or a Banking Company etc. to recover their dues as arrears of land revenue. The provisions contained in the Bill, when enacted, will be implemented through the existing Government machinery and thus for the implementation of the provisions of the Bill, no additional expenditure shall be incurred out of the State exchequer.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 4 of the Bill empowers the State Government to notify the rate of collection charge to be paid to the State Government by the Banking Company, a Corporation or a Government Company availing the services of the Collector.

This delegation is essential and normal in character.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-५ द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित